Test Cloud

Daily करेंट अफेयर्स

29 जुलाई 2025

NATIONAL AFFAIRS

1. PM मोदी ने 2031 तक 1 करोड़ से अधिक प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटल बनाने के लिए 483 करोड़ रुपये के 'ज्ञान भारतम मिशन' का शुभारंभ किया।

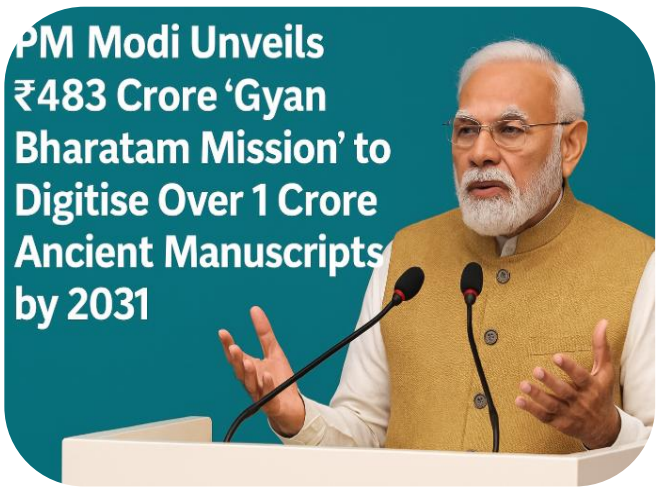

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून, 2025 को राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के पुनर्गठित और विस्तारित संस्करण, ज्ञान भारतम मिशन का औपचारिक उद्घाटन किया। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत इस पहल का उद्देश्य 2031 तक एक करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण और संरक्षण करके एक वैश्विक-सुलभ राष्ट्रीय डिजिटल संग्रह तैयार करना है।

• ज्ञान भारतम मिशन, पूर्व राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन (NMM) का स्थान लेता है, जिसे 2003 में संस्कृति मंत्रालय ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA) के माध्यम से शुरू किया था। इस नए मिशन की घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 के दौरान की गई थी और इसका आधिकारिक शुभारंभ 9 जून, 2025 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुआ था। इसका उद्देश्य पुस्तकालयों, विश्वविद्यालयों, संग्रहालयों और निजी संग्रहों में संग्रहित दस मिलियन (एक करोड़) से अधिक पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, दस्तावेज़ीकरण, संरक्षण और डिजिटलीकरण करना है।

• एक बड़े वित्तीय बदलाव के तहत, पांडुलिपि संरक्षण के लिए वार्षिक बजट को ₹3.5 करोड़ से बढ़ाकर ₹60 करोड़ कर दिया गया है—जो लगभग सत्रह गुना वृद्धि है—यह 2024-2031 तक चलने वाली ₹482.85 करोड़ की एक बड़ी केंद्रीय क्षेत्र योजना का हिस्सा है। संस्कृति मंत्रालय की देखरेख में होने वाला यह वित्तपोषण मिशन के विभिन्न घटकों को सहायता प्रदान करेगा: सर्वेक्षण, संरक्षण, डिजिटलीकरण, शोध प्रकाशन, क्षमता निर्माण और आउटरीच गतिविधियाँ।

• इस मिशन का उद्देश्य राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षणों, वैज्ञानिक संरक्षण और एक राष्ट्रीय डिजिटल पांडुलिपि पुस्तकालय के निर्माण के माध्यम से पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण और संरक्षण करना है। प्रमुख प्रयासों में पांडुलिपि विज्ञान और अनुवाद का प्रशिक्षण शामिल है, और वाराणसी स्थित संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जैसे केंद्र संरक्षण पहलों में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।

Key Points:-

(i) 2025 तक, लगभग 52 लाख पांडुलिपियों का मेटाडेटा तैयार किया जा चुका है, लगभग 3 लाख पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है और लगभग 1.35 लाख ऑनलाइन अपलोड की जा चुकी हैं, जिनमें से केवल 76,000 ही जनता के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध हैं। अगले पाँच वर्षों में, इस मिशन का उद्देश्य डिजिटलीकरण और सार्वजनिक पहुँच, दोनों का महत्वपूर्ण विस्तार करना है, जिसमें दुर्लभ और नाजुक पांडुलिपियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। समय के साथ, और अधिक पांडुलिपियाँ—जिनमें निजी संग्रह में मौजूद पांडुलिपियाँ भी शामिल हैं, जिनमें भारत की पांडुलिपि संपदा का लगभग 80% हिस्सा होने का अनुमान है—को पहुँच-साझाकरण नीतियों के माध्यम से इस संग्रह में लाया जाएगा।

(ii) इस मिशन में विश्वविद्यालयों, शोध केंद्रों, निजी संग्रहकर्ताओं और गूगल आर्ट्स एंड कल्चर जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों के साथ सहयोगात्मक साझेदारियाँ शामिल हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत

की अध्यक्षता में आयोजित विशेषज्ञ परामर्श बैठकों में, उदय नारायण सिंह, के. रामसुब्रमण्यन और सुधा गोपालकृष्णन जैसे विद्वानों ने नीतिगत ढाँचों, मेटाडेटा मानकों और डिजिटलीकरण प्रोटोकॉल को आकार देने में मदद की। नए ढाँचे में बेहतर दक्षता के लिए पूर्ववर्ती IGNCA उप-संरचना के स्थान पर एक स्वायत्त संस्थागत तंत्र की परिकल्पना की गई है।

(iii) स्वामी विवेकानंद के 1893 के संबोधन को याद करते हुए, 11-13 सितंबर, 2025 तक नई दिल्ली में एक तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसमें 500 प्रतिनिधि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित लिपि पहचान, संरक्षण और पुरालेख विज्ञान पर सत्रों के लिए एकत्रित होंगे, जिसमें पांडुलिपि संरक्षण में स्टार्टअप्स और नवाचारों को प्रदर्शित किया जाएगा—प्राचीन भारतीय ज्ञान को आधुनिक विद्वता और कूटनीति के साथ सम्मिश्रित किया जाएगा।

2. भारतीय रेलवे ने दुर्घटनाओं को रोकने के लिए डायरेक्ट ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग (DDEI) प्रणाली का सफलतापूर्वक पायलट परीक्षण किया।

भारतीय रेलवे ने दीनानगर (जम्मू) और ताजपुर (रतलाम मंडल, मध्य प्रदेश) में उन्नत डायरेक्ट ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग (DDEI) प्रणाली के प्रायोगिक परीक्षण पूरे किए हैं। यह प्रणाली सिग्नलिंग विफलताओं और मानवीय भूलों को उल्लेखनीय रूप से कम करने में सक्षम है, जिससे बालासोर रेल दुर्घटना जैसी त्रासदियों को टालने में मदद मिलेगी, जिसमें लगभग 300 लोगों की जान चली गई थी।

• DDEI प्रणाली सिग्नल, ट्रैक और पॉइंट मैकेनिज्म के साथ सीधे इंटरफेस करके पारंपरिक रिले को खत्म कर देती है। इससे विफलता बिंदु कम होते हैं, रखरखाव सरल होता है, और व्यापक तांबे के तारों पर निर्भरता कम होती है, जिससे महत्वपूर्ण सिग्नलिंग बुनियादी ढांचे में विश्वसनीयता बढ़ती है।

• नवंबर 2024 में ताजपुर स्टेशन पर शुरू की गई इस परियोजना को पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया। जापानी फर्म TSTS से तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त यह प्रणाली तेज़ संचालन, बेहतर सुरक्षा और कवच जैसी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणालियों के साथ सहज एकीकरण को सक्षम बनाती है।

• पश्चिमी रेलवे इस जापानी मूल की तकनीक को अपनाने वाला पहला ज़ोन बन गया। ऑप्टिकल फाइबर केबल लगभग 60-70% पारंपरिक तारों की जगह ले लेते हैं और रिले की संख्या लगभग 70% तक कम कर देते हैं, जिससे रखरखाव की लागत कम हो जाती है और सिग्नल प्रबंधन में मानवीय त्रुटि न्यूनतम हो जाती है।

Key Points:-

(i) DDEI प्रणाली भारत की स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (ATP) प्रणाली, कवच के साथ पूरी तरह से संगत है। यह एकीकरण समन्वित सिग्नलिंग और आवश्यकता पड़ने पर आपातकालीन ब्रेकिंग को सक्षम करेगा, जिससे ट्रेन संचालन की समग्र सुरक्षा में सुधार होगा।

(ii) ताजपुर और दीनानगर में सफल परीक्षणों के बाद, भारतीय रेलवे DDEI को अन्य उच्च-घनत्व और उच्च-जोखिम वाले मार्गों पर भी लागू करने की योजना बना रहा है। पायलट कार्यान्वयन सभी क्षेत्रों में प्रगतिशील आधुनिकीकरण का एक मॉडल प्रस्तुत

करता है, जिससे समय की पाबंदी और दुर्घटना रोकथाम में अपेक्षित लाभ होगा।

(iii) यह विकास कवच प्रणाली के चल रहे विस्तार का पूरक है - जिसे भारत के राष्ट्रीय ATP के रूप में अनुमोदित किया गया है और उच्चतम सुरक्षा अखंडता स्तर (SIL-4) पर प्रमाणित किया गया है - जिसे टकराव और सिग्नल-पासिंग त्रुटियों को रोकने के लिए पहले से ही हजारों किलोमीटर ट्रैक पर तैनात किया गया है।

3. मंगलुरु की लड़की रेमोना परेरा ने 170 घंटे तक लगातार भरतनाट्यम प्रस्तुति देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया।

जुलाई 2025 में, कर्नाटक के मंगलुरु स्थित सेंट एलॉयसियस (डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी) में बीए तृतीय वर्ष की छात्रा रेमोना एवेट परेरा ने 21 जुलाई से सात दिनों तक लगातार भरतनाट्यम मैराथन शुरू की। उनका लक्ष्य: 170 घंटे के शानदार प्रदर्शन के साथ गोल्डन बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराना।

• रेमोना का रिकॉर्ड बनाने का प्रयास आधिकारिक तौर पर 21 जुलाई को सुबह 10:30 बजे उनके कॉलेज परिसर स्थित रॉबर्ट सेक्वेरा हॉल में शुरू हुआ, जो चौबीसों घंटे चलता रहेगा और हर तीन घंटे में केवल 15 मिनट का ब्रेक मिलेगा, जिसमें हल्का भोजन और आराम शामिल होगा। यह प्रदर्शन 28 जुलाई को दोपहर 1 बजे समाप्त होगा, जो पूरे 170 घंटे चलेगा।

• इस असाधारण उपलब्धि की तैयारी के लिए, रेमोना ने सौरभ कला परिषद में गुरु डॉ. श्रीविद्या मुरलीधर के अधीन 13 वर्षों से अधिक समय तक प्रशिक्षण लिया। उन्होंने एक अनुशासित दिनचर्या बनाए रखी—प्रतिदिन 5-6 घंटे अभ्यास, पढ़ाई और नृत्य के बीच संतुलन बनाए रखते हुए—सुबह 6:00 बजे से 7:30 बजे तक, और फिर शाम 6:00 बजे से 9:00 बजे तक।

• रेमोना राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त एक प्रतिष्ठित कलाकार हैं। उन्हें 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इंडिया बुक ऑफ़ रिकॉर्ड्स, गोल्डन बुक ऑफ़ रिकॉर्ड्स (लंदन) और भारत बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स (2017) में भी उनका नाम दर्ज है। उनके प्रदर्शनों की सूची में शास्त्रीय, अर्ध-शास्त्रीय, लोक, हिप-हॉप और एक्रोबैटिक शैलियाँ शामिल हैं, जिनमें अक्सर टूटे हुए काँच पर नृत्य या अग्निपात्रों को संतुलित करने जैसे साहसिक तत्व शामिल होते हैं।

Key Points:-

(i) सबसे लंबे भरतनाट्यम प्रदर्शन का वर्तमान गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड 127 घंटे का है, जो 2023 में महाराष्ट्र के लातूर की सृष्टि सुधीर जगताप ने बनाया है। रेमोना का लक्ष्य इस रिकॉर्ड को 40 घंटे से भी ज़्यादा लंबा करके शास्त्रीय नृत्य के धीरज के रिकॉर्ड में भारत की विरासत को मज़बूती से आगे बढ़ाना है।

(ii) यह मैराथन न केवल सहनशक्ति की परीक्षा है, बल्कि एक सांस्कृतिक श्रद्धांजलि भी है। रेमोना ने भक्तिमय दृश्यों को शामिल किया—पहले दिन भगवान गणेश की प्रार्थना से शुरू होकर सातवें दिन देवी दुर्गा की वंदना के साथ समापन—जिन्हें अलारिप्पु, जतिस्वरम, वर्णम, पदम और तिल्लाना जैसी पारंपरिक भरतनाट्यम रचनाओं में पिरोया गया।

(iii) इस प्रयास को समुदाय का भरपूर समर्थन मिला। ज़िला प्रभारी मंत्री दिनेश गुंडू राव, MLC इवान डिसूज़ा, विधायक वेदव्यास कामथ, उपायुक्त दर्शन के.वी. और ज़िला पंचायत के CEO नरवड़े विनायक करभारी जैसे प्रमुख गणमान्य व्यक्ति कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित थे। उनकी माँ ग्लेडिस परेरा और स्वयंसेवकों की एक समर्पित टीम ने पूरे सप्ताह उनका मनोबल बनाए रखा। गोल्डन बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के निर्णायकों द्वारा इस प्रयास के पूरा होने पर इसकी पुष्टि किए जाने की उम्मीद है।

4. NALSA ने रक्षा कर्मियों और परिवारों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए 'वीर परिवार सहायता 2025' शुरू किया।

जुलाई 2025 में, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय और जम्मू-कश्मीर विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से रक्षा कर्मियों और उनके परिवारों के लिए मुफ्त और समय पर कानूनी सहायता सुनिश्चित करने के लिए 'वीर परिवार सहायता 2025' योजना शुरू की।

• यह योजना आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति सूर्यकांत द्वारा शुरू की गई, जो जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर स्थित शेर-ए-कश्मीर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र (SKICC) में आयोजित उत्तर क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान लॉन्च की गई। इस सम्मेलन का शीर्षक था 'रक्षा कर्मियों और जनजातीयों के लिए संविधानिक न्याय की दृष्टि को पुनः पुष्टि करना'।

• 'वीर परिवार सहायता 2025' को रक्षा कर्मियों और उनके परिवारों को संपत्ति विवाद, पारिवारिक मामलों, भूमि स्वामित्व और घरेलू हिंसा से संबंधित कानूनी मुद्दों को हल करने में सहायता करने के लिए डिज़ाइन किया गया है - विशेष रूप से उन मामलों में जहां कर्मियों को जम्मू और कश्मीर और उत्तर पूर्व क्षेत्र (NER) जैसे दूरस्थ या उच्च तनाव वाले क्षेत्रों में तैनात किया जाता है।

• यह योजना न केवल सेना के जवानों को बल्कि सीमा सुरक्षा बल (BSF), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) सहित अर्धसैनिक बलों को भी कठिन इलाकों में तैनाती के कारण आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए कानूनी सहायता प्रदान करेगी।

Key Points:-

(i) इस योजना का एक मुख्य घटक जिला सैनिक बोर्डों, राज्य सैनिक बोर्डों और केंद्रीय सैनिक बोर्डों में कानूनी सेवा क्लीनिकों का एक संरचित नेटवर्क स्थापित करना है। ये क्लीनिक शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सैन्य परिवारों के लिए अग्रणी कानूनी सहायता केंद्र के रूप में कार्य करेंगे।

(ii) NALSA विभिन्न क्षेत्रों में विशेष रूप से प्रशिक्षित नोडल अधिकारियों, कानूनी सहायता सलाहकारों और अर्ध-कानूनी स्वयंसेवकों—जिनमें पूर्व सैनिक भी शामिल हैं—को समय पर, ज़मीनी सहायता प्रदान करने के लिए तैनात करेगा। इस प्रशिक्षित कार्यबल से प्रभावित परिवारों और न्याय व्यवस्था के बीच एक सीधे सेतु के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की जाती है।

(iii) सुगम्यता और गति सुनिश्चित करने के लिए, इस योजना के अंतर्गत डिजिटल एकीकरण को

प्राथमिकता दी गई है। नालसा ई-लोक अदालतों और ऑनलाइन मध्यस्थता प्लेटफार्मों के उपयोग को बढ़ावा देगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि कानूनी सेवाएँ डिजिटल रूप से और बिना किसी भौतिक यात्रा के बोझ के, सबसे दूरस्थ क्षेत्रों तक भी पहुँचें।

5. ओडिशा के मुख्यमंत्री ने भुवनेश्वर में पहली बार ODISHA TEX2025 का उद्घाटन किया, ₹7,808 करोड़ के कपड़ा निवेश लहर का अनावरण किया।

जुलाई 2025 में, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने भुवनेश्वर के लोक सेवा भवन स्थित राज्य सम्मेलन केंद्र में पूर्वी भारत के पहले कपड़ा निवेश शिखर सम्मेलन, ओडिशा टेक्स 2025 का उद्घाटन किया। इस ऐतिहासिक आयोजन ने ओडिशा के एक कपड़ा महाशक्ति के रूप में उभरने को प्रदर्शित किया, 650 से अधिक प्रतिनिधियों को आकर्षित किया और महत्वपूर्ण निवेश एवं रोज़गार प्रतिबद्धताओं को जन्म दिया।

• ओडिशा टेक्स 2025 का आधिकारिक शुभारंभ 25 जुलाई, 2025 को भुवनेश्वर में हुआ, जो कपड़ा, परिधान, तकनीकी वस्त्र, जूते और सहायक उपकरण उद्योग को समर्पित ओडिशा का पहला बड़े पैमाने का उद्योग सम्मेलन था। यह कार्यक्रम राज्य सम्मेलन केंद्र, लोक सेवा भवन में आयोजित किया गया और इसका औपचारिक उद्घाटन मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने उद्योग मंत्री संपद चंद्र स्वैन, सहकारिता मंत्री प्रदीप बाल सामंत और राज्य के प्रमुख अधिकारियों की उपस्थिति में किया।

• CM माझी ने ओडिशा की "पूर्वी भारत का कपड़ा केंद्र" बनने की महत्वाकांक्षा की घोषणा की, क्योंकि इस शिखर सम्मेलन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों, वैश्विक ब्रांडों, स्टार्टअप्स, कपड़ा कंपनियों और सरकारी अधिकारियों सहित 650 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तिरुपुर, बेंगलुरु, सूरत, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और पश्चिम बंगाल जैसे कपड़ा केंद्रों की भागीदारी ने इस आयोजन की अखिल भारतीय अपील को रेखांकित किया।

• शिखर सम्मेलन के दौरान, ओडिशा ने उद्योग जगत के नेताओं - पेज इंडस्ट्रीज, केपीआर मिल्स, स्पोर्ट्सकिंग इंडिया, फर्स्ट स्टेप बेबीवियर और हिंडाल्को जैसी प्रमुख कंपनियों के साथ 33 समझौता ज्ञापनों (MoU) पर हस्ताक्षर किए - जिससे 7,808 करोड़ रुपये के निवेश के इरादे सामने आए और कपड़ा और परिधान क्षेत्रों में 53,300 से अधिक नौकरियों के सृजन का वादा किया गया।

Key Points:-

(i) एक प्रमुख पहल की घोषणा की गई, जिसमें बोलांगीर, क्योंझर, संबलपुर, जगतसिंहपुर, गंजम और कटक सहित जिलों में छह नए कपड़ा, परिधान और फुटवियर पार्कों का शुभारंभ शामिल था। इन पार्कों में प्लग-एंड-प्ले बुनियादी ढाँचा है, जिसे वैश्विक और घरेलू निर्माताओं को आकर्षित करने और आपूर्ति-श्रृंखला दक्षता बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

(ii) मुख्यमंत्री माझी ने ओडिशा परिधान एवं तकनीकी वस्त्र नीति 2022 (OATTP-2022) के अंतर्गत संशोधित रोज़गार सब्सिडी का भी अनावरण किया: पुरुष श्रमिकों के लिए सब्सिडी ₹5,000 से बढ़ाकर ₹6,000 प्रति माह और महिला श्रमिकों के लिए

₹6,000 से बढ़ाकर ₹7,000 प्रति माह कर दी गई। परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेज़ी लाने के लिए उद्योग विभाग के अंतर्गत एक समर्पित टास्क फोर्स का गठन किया गया।

(iii) अतिरिक्त मुख्य सचिव हेमंत शर्मा ने ओडिशा की समावेशी औद्योगिक रणनीति पर ज़ोर दिया, जिसमें राज्य के कुशल कार्यबल—विशेषकर तिरुपुर और सूरत जैसे केंद्रों से लौटने वाले प्रवासी कारीगरों—का लाभ उठाया जाएगा और पारंपरिक शिल्प को आधुनिक तकनीक के साथ एकीकृत किया जाएगा। शर्मा ने डिजिटल स्वीकृतियों के लिए "गो स्विफ्ट 2.0" और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय MSME पार्कों जैसे चल रहे सुधारों पर प्रकाश डाला। यह शिखर सम्मेलन व्यापक पूर्वोदय भारत दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य ओडिशा को 2030-31 तक 1 लाख से ज़्यादा कपड़ा उद्योग में रोज़गार सृजित करने की दिशा में ले जाना है।

INTERNATIONAL

1. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मालदीव की दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा संपन्न की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और मालदीव के बीच राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 25 से 26 जुलाई, 2025 तक मालदीव की दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा की। इस यात्रा ने सांस्कृतिक समारोहों, रक्षा सहयोग और प्रमुख बुनियादी ढाँचे के उद्घाटन के माध्यम से द्विपक्षीय सहयोग को और मज़बूत किया।

• यह यात्रा 2014 में पदभार ग्रहण करने के बाद से प्रधानमंत्री मोदी की मालदीव की तीसरी आधिकारिक यात्रा थी। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्ज़ू ने माले के वेलाना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया, जो दोनों देशों के बीच मजबूत कूटनीतिक गर्मजोशी और संबंधों में निरंतरता का प्रतीक है।

• अपनी यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी 26 जुलाई, 2025 को मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हुए, और इस कार्यक्रम के लिए "सम्मानित अतिथि" के रूप में आमंत्रित होने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने, जो माले के रिपब्लिक स्क्वायर में आयोजित किया गया था।

• 25 जुलाई, 2025 को, दोनों नेताओं ने राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। इस डाक टिकट पर केरल के बेयपोर में हस्तनिर्मित भारतीय नाव उरु और दोनों देशों की साझा समुद्री संस्कृति के प्रतीक मालदीव की 'वधू धोनी' को दर्शाया गया है।

Key Points:-

(i) प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने संयुक्त रूप से माले में भारत की सहायता से निर्मित रक्षा मंत्रालय के नए धोशिमेना भवन का उद्घाटन किया। यह परियोजना मालदीव के रक्षा बुनियादी ढाँचे और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए भारत के निरंतर समर्थन का प्रतीक है।

(ii) रक्षा सहयोग के अलावा, प्रधानमंत्री मोदी ने मालदीव में भारत द्वारा वित्त पोषित विभिन्न बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया, जिसमें सड़क निर्माण और 5,000 करोड़ रुपये की उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं

(HICDP) के तहत निवेश शामिल हैं।

(iii) मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल (MNDF) ने भी प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान उन्हें सम्मानित किया तथा मानवीय और रक्षा सहयोग के माध्यम से मालदीव की संप्रभुता, समुद्री क्षमता और क्षेत्रीय शांति को समर्थन देने में भारत की दीर्घकालिक भूमिका को स्वीकार किया।

2. तुर्की ने इस्तांबुल में IDEF 2025 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर-परमाणु बम 'Gazap' का अनावरण किया।

तुर्की ने इस्तांबुल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रक्षा उद्योग मेले (IDEF) 2025 में अपने सबसे शक्तिशाली गैर-परमाणु बम, गज़ैप का अनावरण किया है। इस उन्नत थर्मोबैरिक बम का प्रक्षेपण तुर्की की स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमताओं में एक बड़ी छलांग का प्रतीक है, जो इसे वैश्विक स्तर पर गैर-परमाणु हथियार प्रौद्योगिकी में अग्रणी देशों में शामिल करता है।

• गजप बम का वजन लगभग 970 किलोग्राम है और यह प्रति मीटर 10.16 घातक टुकड़े फैलाता है, जो इस श्रेणी के पारंपरिक बमों से लगभग तीन गुना अधिक है।

• यह उन्नत विखंडन प्रणाली एक व्यापक मारक दायरा बनाती है, जिससे उच्च तीव्रता वाली युद्ध स्थितियों में, विशेष रूप से शहरी और किलेबंद वातावरण में, इसकी प्रभावशीलता बढ़ जाती है।

• थर्मोबैरिक तकनीक से निर्मित, गज़ैप 3,000°C तक का तापमान उत्पन्न कर सकता है, जिससे यह एक बड़े दायरे में अत्यधिक संरचनात्मक और मानवीय क्षति पहुँचाने में सक्षम है। यह बम विमान-संगत है, जिसे F-16 और F-4 विमानों के माध्यम से तैनात करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, और तुर्की अधिकारियों के अनुसार, निकट भविष्य में इसे ड्रोन द्वारा तैनात करने योग्य बनाने के प्रयास चल रहे हैं, जिससे इसकी सामरिक बहुमुखी प्रतिभा का उल्लेखनीय विस्तार होगा।

Key Points:-

(i) इसी कार्यक्रम के दौरान, तुर्की के रक्षा उद्योग ने NEB-2 घोस्ट का भी प्रदर्शन किया, जो एक गहरी पैठ वाला बंकर-बस्टर बम है जो 7 मीटर गहरे कंक्रीट को भेदने में सक्षम है। इस हथियार को भूमिगत बंकरों और किलेबंद आश्रयों को निशाना बनाने के लिए विकसित किया गया है, जिससे तुर्की की रणनीतिक सटीक हमले करने की क्षमता बढ़ जाती है।

(ii) गज़ैप और NEB-2 घोस्ट, दोनों को तुर्की की राष्ट्रीय रक्षा पहल के तहत, रक्षा उद्योग प्रेसीडेंसी (SSB) और राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय (MSB) के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका अनावरण तुर्की के रक्षा मंत्री यासर गुलर की उपस्थिति में हुआ, जिन्होंने अगली पीढ़ी के पारंपरिक निवारक हथियार स्थापित करने की तुर्की की महत्वाकांक्षाओं पर ज़ोर दिया।

(iii) ये हालिया अनावरण तुर्की की बढ़ती रक्षा महत्वाकांक्षाओं और अंतरराष्ट्रीय अप्रसार मानदंडों का उल्लंघन किए बिना परमाणु-प्रभाव वाले हथियार बनाने की उसकी क्षमता को रेखांकित करते हैं। आईडीईएफ 2025 मंच ने एक बार फिर राष्ट्रीय और संबद्ध सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक सैन्य विज्ञान को तैनाती योग्य हथियार प्रणालियों में एकीकृत करने की तुर्की की क्षमता का प्रदर्शन किया है।

BANKING & FINANCE

1. मास्टरकार्ड ने राज्य भर में पर्यटन अनुभव को बेहतर बनाने के लिए आंध्र प्रदेश के साथ साझेदारी की है।

जुलाई 2025 में, आंध्र प्रदेश पर्यटन विभाग ने विजयवाड़ा में एक रणनीतिक कार्यशाला आयोजित करने के लिए मास्टरकार्ड के साथ हाथ मिलाया। इस सहयोग का उद्देश्य मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के दृष्टिकोण के तहत, व्यापक पर्यटन सर्किट विकसित करना, एक विशिष्ट राज्यव्यापी ब्रांड पहचान बनाना और मास्टरकार्ड धारकों और वैश्विक यात्रियों के लिए डिजिटल पहुँच को बढ़ाना है।

- **विजयवाड़ा में, आंध्र प्रदेश पर्यटन विकास निगम (APTDC) के अधिकारियों ने मास्टरकार्ड के प्रतिनिधियों और पर्यटन हितधारकों के साथ मिलकर एक कार्यशाला आयोजित की, जिसमें विश्वस्तरीय पर्यटन अनुभव तैयार किए गए। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य तटीय और आदिवासी विरासत से लेकर आध्यात्मिक स्थलों तक, विषयगत पर्यटन सर्किट तैयार करना और उन्हें मास्टरकार्ड कार्डधारकों और अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों की वैश्विक अपेक्षाओं के अनुरूप बनाना था।**

- **मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू, पर्यटन मंत्री कंदुला दुर्गेश और विशेष मुख्य सचिव अजय जैन के मार्गदर्शन में, राज्य आंध्र प्रदेश को दक्षिण एशिया के शीर्ष पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने की दिशा में काम कर रहा है। विकास के विषयों में डिजिटल मार्केटिंग एकीकरण, व्यापक ब्रांडिंग और सितंबर में विश्व पर्यटन दिवस पर लॉन्च की जाने वाली एक अनूठी पर्यटन टैगलाइन की अवधारणा शामिल है।**

Key Points:-

(i) हितधारकों ने टिकाऊ पर्यटन मॉडल पर चर्चा की जो अराकू-विशाखापत्तनम (आदिवासी संस्कृति), गोदावरी बैकवाटर, सूर्यलंका-चिराला तटीय सर्किट और तिरुपति आध्यात्मिक गलियारे जैसे स्थलों के भीतर स्थानीय समुदायों और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को एकीकृत करते हैं।

(ii) यह साझेदारी आंध्र प्रदेश के पर्यावरण-पर्यटन और समुदाय-आधारित पहलों पर आधारित है। राज्य ने आदिवासी, विरासत, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 500 से ज़्यादा नए होमस्टे चिन्हित किए हैं—जिनका अगस्त 2025 तक नवीनीकरण किया जाएगा—और तिरुपति में लगभग 600 मौजूदा होमस्टे एयरबीएनबी, ओयो और मेकमाईट्रिप जैसे प्लेटफ़ॉर्म के सहयोग से आतिथ्य प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। मास्टरकार्ड का सहयोग समावेशी विकास और विकेंद्रीकृत पर्यटन आजीविका के इस केंद्र को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

2. जून 2025 तक भारत की अघोषित बैंक जमा राशि 67,003 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगी।

संसद में साझा की गई जानकारी के अनुसार, 30 जून, 2025 तक, भारत भर के बैंकों के पास ₹67,003 करोड़ की अघोषित जमा राशि थी—खाताधारकों या दावेदारों द्वारा किसी भी दावे के बिना निष्क्रिय पड़ी हुई धनराशि। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने नागरिकों को इस धनराशि को कुशलतापूर्वक पुनः प्राप्त करने में मदद करने के लिए डिजिटल उपकरण और सुधार शुरू किए हैं।

• दावा न किए गए जमा से तात्पर्य बचत, सावधि या आवर्ती बैंक खातों में जमा राशि से है जो 10 वर्षों से अधिक समय से निष्क्रिय हैं और खाताधारक या उनके नामिती द्वारा उनसे कोई निकासी, जमा या सूचना नहीं दी गई है। ऐसे निष्क्रिय खातों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक के नियमों के तहत निष्क्रिय के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

• जून 2025 तक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास ₹58,330.26 करोड़ की अघोषित जमा राशि के साथ सबसे बड़ा हिस्सा था, जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों के पास ₹8,673.72 करोड़ जमा थे। सार्वजनिक बैंकों में, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ₹19,329.92 करोड़ के साथ सबसे आगे रहा, उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक (₹6,910.67 करोड़) और केनरा बैंक (₹6,278.14 करोड़) का स्थान रहा। निजी बैंकों में, ICICI बैंक ₹2,063.45 करोड़ के साथ शीर्ष पर रहा।

Key Points:-

(i) भारतीय रिज़र्व बैंक की भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट, 2023-24 के अनुसार, मार्च 2024 तक अघोषित जमा राशि बढ़कर ₹78,213 करोड़ हो गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 26% अधिक है। यह राशि जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता (DEA) कोष का हिस्सा है, जिसका उपयोग जमाकर्ता जागरूकता पहलों और अघोषित धन की सुरक्षा के लिए किया जाता है।

(ii) बढ़ती निष्क्रियता के जवाब में, RBI ने अगस्त 2023 में UDGAM पोर्टल (अदावाकृत जमाएँ - सूचना तक पहुँच का प्रवेश द्वार) लॉन्च किया, जिससे उपयोगकर्ता अपने नाम, बैंक के नाम या अदावाकृत जमा संदर्भ संख्या (UDRN) के माध्यम से कई बैंकों में अदावाकृत जमाओं की खोज कर सकेंगे। जुलाई 2025 की शुरुआत तक, UDGAM पर 859,683 से अधिक उपयोगकर्ता पंजीकृत हो चुके हैं।

(iii) नागरिकों को निष्क्रिय धन वापस पाने में मदद करने के लिए, मई-जून 2025 में जारी RBI के नए दिशानिर्देश ग्राहकों को किसी भी बैंक शाखा में अपने ग्राहक को जानें (KYC) विवरण अपडेट करने, वीडियो KYC का उपयोग करने, या विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, व्यवसाय संवाददाताओं से सहायता प्राप्त करने की अनुमति देते हैं। इन सुधारों का उद्देश्य प्रक्रियात्मक बाधाओं को कम करना और धन की त्वरित वसूली को सक्षम बनाना है।

ECONOMY & BUSINESS

1. भारत में 2017-18 से 17 करोड़ नौकरियों में वृद्धि हुई है और महिला श्रम बल भागीदारी 41.7% के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई।

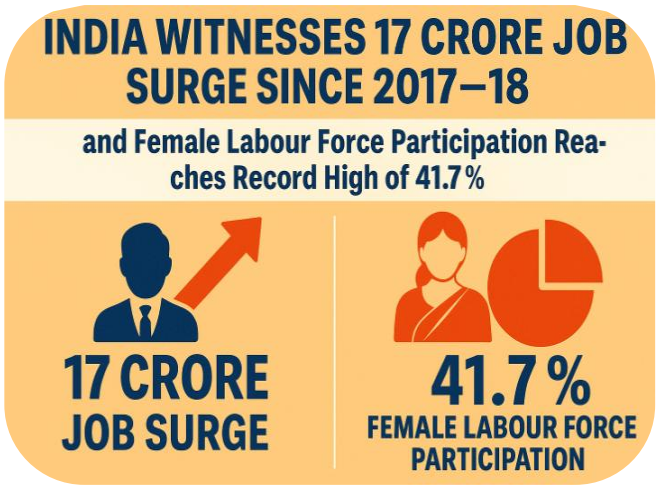

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने लोकसभा में बताया कि वित्त वर्ष 2017-18 और 2023-24 के बीच, भारत में 17 करोड़ नौकरियाँ जुड़ीं, जिससे कुल रोज़गार लगभग 47.5 करोड़ से बढ़कर 64.3 करोड़ हो गया। उल्लेखनीय है कि महिला श्रमबल में भागीदारी 40% से अधिक हो गई है और युवा बेरोज़गारी में उल्लेखनीय कमी आई है।

• विश्व बैंक की एक रिपोर्ट बताती है कि 2021-22 से भारत में रोज़गार की वृद्धि कार्यशील आयु वर्ग की आबादी की तुलना में तेज़ी से हुई है। वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में शहरी बेरोज़गारी घटकर 6.6% रह गई, जो 2017-18 के बाद से सबसे निचला स्तर है। हाल के वर्षों में महिला रोज़गार और स्व-रोज़गार—खासकर ग्रामीण महिलाओं में—दोनों में वृद्धि हुई है।

• प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) के अनुसार, ग्रामीण FLFPR (महिला श्रम बल भागीदारी दर) 2017-18 में 24.6% से बढ़कर 2022-23 में 41.5% हो गया, जबकि शहरी FLFPR 20.4% से बढ़कर 25.4% हो गया। PLFS के आंकड़ों के अनुसार, जून 2024 में समग्र राष्ट्रीय FLFPR 41.7% तक पहुँच गया, जो ग्रामीण महिलाओं द्वारा संचालित एक नाटकीय वृद्धि को दर्शाता है।

• आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में बताया गया है कि महिलाओं में स्व-रोज़गार 2017-18 के 52.2% से बढ़कर 2023-24 में 58.4% हो गया है। हालाँकि यह बढ़ती आर्थिक भागीदारी को दर्शाता है, लेकिन विशेषज्ञ आगाह करते हैं कि इनमें से ज़्यादातर भूमिकाएँ अनौपचारिक या कम वेतन वाले क्षेत्रों में हैं—केवल 15.9% कामकाजी महिलाएँ ही अब नियमित वेतन या वेतन वाली नौकरियाँ कर रही हैं।

Key Points:-

(i) समग्र रोज़गार वृद्धि के बावजूद, युवा बेरोज़गारी एक चुनौती बनी हुई है, जिसकी दर 13.3% है, और डिग्री धारकों में तो यह और भी ज़्यादा (29%) है। इस बीच, लैंगिक वेतन अंतर बना हुआ है: स्व-रोज़गार वाली महिलाएँ पुरुषों की तुलना में लगभग एक-तिहाई कमाती हैं, और केवल 23% गैर-कृषि नौकरियाँ औपचारिक हैं।

(ii) मुद्रा ऋण, ड्रोन दीदी, दीनदयाल अंत्योदय योजना (DAY-NRLM), स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड (SIB) जैसे परिणाम-आधारित कौशल मॉडल और स्टार्टअप इंडिया के तहत उद्यमिता कार्यक्रमों जैसी योजनाओं ने समावेशन को बढ़ावा दिया है। अक्टूबर 2024 तक कम से कम एक महिला निदेशक वाले 73,151 से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत किए गए।

(iii) उत्साहजनक रुझानों के बावजूद, भारत में महिलाओं की भागीदारी G20 के औसत से पीछे है। रॉयटर्स के एक सर्वेक्षण के अनुसार, भारत को लगभग 50% महिला LFPR के वैश्विक औसत तक पहुँचने में 20-30 वर्ष लग सकते हैं। विशेषज्ञ प्रगति को बनाए रखने के लिए सुरक्षित कार्यस्थलों, सुलभ बाल देखभाल, भेदभाव-विरोधी कानूनों, परिवहन अवसंरचना और औपचारिकता की आवश्यकता पर बल देते हैं।

SPORTS

1. ऑस्कर पियास्ट्री ने 2025 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जीता और मैकलारेन ने शीर्ष दो स्थान हासिल किए।

27 जुलाई 2025 को ऑस्ट्रेलियाई फॉर्मूला वन (F1) ड्राइवर ऑस्कर पियास्त्री ने बेल्जियम के सर्किट डी स्पा-फ्रैंकोरशॉम्प्स (Circuit de Spa-Francorchamps) में आयोजित 70वीं बेल्जियन ग्रां प्री में शानदार जीत दर्ज की। यूनाइटेड किंगडम (UK) की टीम मैकलेरन के लिए रेस करते हुए उन्होंने टीममेट लैंडो नॉरिस के साथ वन-टू फिनिश दर्ज कराकर मौजूदा एफ1 सीज़न में मैकलेरन की दबदबा साबित किया।

• यह जीत पियास्त्री के लिए इस सीज़न की 13 में से छठी जीत रही, जिससे उन्होंने फॉर्मूला वन वर्ल्ड चैम्पियनशिप (F1 World Championship) में अपनी बढ़त को 16 अंकों तक बढ़ा लिया है, जो अब टीममेट लैंडो नॉरिस से आगे है।

• यह रेस बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स का 70वां संस्करण था, जो फेडरेशन इंटरनेशनेल डी ला ऑटोमोबाइल (FIA) फॉर्मूला वन विश्व चैम्पियनशिप कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण आयोजन था, और यह प्रतिष्ठित स्पा-फ्रैंकोरचैम्प्स सर्किट में मिश्रित गीली-सूखी परिस्थितियों में आयोजित किया गया था।

• लैंडो नॉरिस ने शुरुआत में पिछड़ने के बाद जबरदस्त वापसी करते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि चार्ल्स लेक्लर (Charles Leclerc) ने फेरारी (Ferrari) के लिए तीसरे स्थान पर रहते हुए पोडियम पूरा किया।

Key Points:-

(i) यह रेस मैकलेरन की लगातार तीसरी वन-टू फिनिश थी, जो दर्शाता है कि टीम इस सीज़न में कार प्रदर्शन और रणनीति दोनों में उत्कृष्ट है। टीम प्रमुख (Team Principal) आंद्रेआ स्टेला (Andrea Stella) के नेतृत्व में यह प्रदर्शन रहा।

(ii) नीदरलैंड्स के मैक्स वर्स्टापेन (Max Verstappen) ने रेड बुल रेसिंग (Red Bull Racing) के लिए चौथा स्थान प्राप्त किया, जो कि क्रिश्चियन हॉर्नर (Christian Horner) के टीम प्रमुख पद से इस्तीफा देने के बाद उनकी पहली रेस थी। वहीं, लुईस हैमिल्टन (Lewis Hamilton) ने मर्सिडीज (Mercedes) के लिए 18वें स्थान से शुरू होकर सातवां स्थान प्राप्त किया।

(iii) अंतिम पोडियम पर विजेता रहे: ऑस्कर पियास्त्री (मैकलेरन, यूनाइटेड किंगडम), लैंडो नॉरिस (मैकलेरन, यूनाइटेड किंगडम), और चार्ल्स लेक्लर (फेरारी, मोनाको)। यह परिणाम कंस्ट्रक्टर्स चैम्पियनशिप और 2025 एफ1 ड्राइवर्स टाइटल की दौड़ में बड़ा बदलाव लाने वाला है।

2. हॉकी इंडिया ने तमिलनाडु में 15वीं कांग्रेस की मेजबानी की और भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रव्यापी समारोह का शुभारंभ किया।

जुलाई 2025 में, हॉकी इंडिया ने भारतीय हॉकी की राष्ट्रीय संस्था के गठन के ऐतिहासिक 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में तमिलनाडु के महाबलीपुरम में अपनी 15वीं हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बुनियादी ढाँचे, वित्तीय अनुदान और 7 नवंबर, 2025 को एक भव्य शताब्दी समारोह पर केंद्रित प्रमुख घोषणाएँ शामिल थीं।

• भारतीय हॉकी महासंघ (IHF), जो भारत में हॉकी की मूल नियामक संस्था है, का आधिकारिक गठन 7 नवंबर, 1925 को ग्वालियर, मध्य प्रदेश में हुआ था। 2025 में होने वाला यह अधिवेशन भारतीय खेल इतिहास में इस महत्वपूर्ण मील के पत्थर की एक शताब्दी का प्रतीक होगा।

• 2008 में प्रशासनिक चिंताओं के कारण IHF के निलंबन के बाद, भारतीय ओलंपिक संघ ने 20 मई 2009 को पुरुष और महिला हॉकी दोनों के लिए एकीकृत राष्ट्रीय शासी निकाय के रूप में हॉकी इंडिया की स्थापना की, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करता है।

• शताब्दी समारोह के एक भाग के रूप में, हॉकी इंडिया ने 7 नवंबर, 2025 को राष्ट्रव्यापी हॉकी महोत्सव की घोषणा की है। इस ऐतिहासिक आयोजन में 1,000 मैच शामिल होंगे - भारत के 500 से अधिक जिलों में से प्रत्येक में एक पुरुष और एक महिला मैच।

Key Points:-

(i) इस विशाल समारोह में 36,000 से ज़्यादा खिलाड़ी शामिल होंगे, जिनमें 18,000 पुरुष और 18,000 महिलाएँ शामिल हैं। इस पहल का उद्देश्य भारत भर में हर प्रशासनिक स्तर पर समावेशिता, ज़मीनी स्तर पर भागीदारी और हॉकी की दृश्यता को बढ़ावा देना है।

(ii) इस पहल को समर्थन देने के लिए, हॉकी इंडिया ने एक संशोधित वित्तीय सहायता योजना की घोषणा की है। सीनियर पुरुष और सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप के प्रत्येक मेजबान को अब ₹70 लाख मिलेंगे, जिससे राष्ट्रीय टूर्नामेंटों के पैमाने और गुणवत्ता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

(iii) इसके अलावा, जूनियर पुरुष, जूनियर महिला, सब-जूनियर पुरुष और सब-जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए प्रत्येक राज्य को ₹30 लाख आवंटित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, जिला और राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु प्रत्येक राज्य को ₹25 लाख प्रदान किए जाएँगे, जिससे व्यापक पहुँच और बुनियादी ढाँचे में वृद्धि सुनिश्चित होगी।

3. दिव्यांशी भौमिक ने 2025 एशियाई युवा टीटी चैंपियनशिप में अंडर-15 बालिका एकल स्वर्ण जीतकर इतिहास रच दिया।

जुलाई 2025 में, भारत की 14 वर्षीय दिव्यांशी भौमिक ने उज़्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित 29वीं एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में अंडर-15 बालिका एकल वर्ग का स्वर्ण पदक जीतकर भारतीय टेबल टेनिस में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। इस वर्ग में भारत का 36 साल का सूखा समाप्त हुआ। उन्होंने आगामी विश्व युवा चैंपियनशिप के लिए भी क्वालीफाई किया।

• दिव्यांशी 36 वर्षों में एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में अंडर-15 बालिका एकल का खिताब

जीतने वाली पहली भारतीय बनीं। पिछली भारतीय चैंपियन सुब्रमण्यम भुवनेश्वरी थीं, जिन्होंने 1989 में नई दिल्ली में यह खिताब जीता था। यह जीत अंतरराष्ट्रीय युवा टेबल टेनिस में भारत के सफर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

• टूर्नामेंट में दूसरी वरीयता प्राप्त दिव्यांशी ने तीन शीर्ष चीनी खिलाड़ियों को हराया, जिसमें फाइनल में झू किही (4-2) और सात गेमों के रोमांचक सेमीफाइनल में लियू ज़िलिंग शामिल थे, उन्होंने महाद्वीपीय स्तर पर दबाव में मानसिक लचीलापन और शीर्ष स्तर के खेल का प्रदर्शन किया।

• उनके स्वर्ण-विजेता प्रदर्शन ने उन्हें नवंबर 2025 में रोमानिया में होने वाली विश्व युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में स्थान दिलाया, जिससे विश्व मंच पर उनके उभरने और वैश्विक जूनियर टीटी परिस्थितियों में भारत की बढ़ती उपस्थिति का संकेत मिला।

Key Points:-

(i) दिव्यांशी दानी स्पोर्ट्स फाउंडेशन की देन है, जो अल्टीमेट टेबल टेनिस (UTT) जूनियर्स प्रोग्राम के साथ-साथ स्काउटिंग और प्रशिक्षण प्रक्रिया का हिस्सा है। अप्रैल 2025 में महाराष्ट्र में टेबल टेनिस सुपर लीग (TTSL) में उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी (ओवरऑल) भी चुना गया, जिससे उनकी घरेलू साख और मजबूत हुई।

(ii) भारत ने ताशकंद चैंपियनशिप में कुल चार पदक जीते: एक स्वर्ण (दिव्यांशी), एक रजत (अंडर-15 बालक टीम) और दो कांस्य पदक (अंडर-19 बालक टीम और अंडर-19 मिश्रित युगल), जो युवा श्रेणियों में मजबूत गहराई और निरंतरता का संकेत देते हैं।

IMPORTANT DAYS

1. विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 2025 पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 28 जुलाई को विश्व स्तर पर मनाया गया ।

विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस (WNCD) 28 जुलाई, 2025 को विश्व स्तर पर मनाया गया ताकि एक स्थायी और पारिस्थितिक रूप से संतुलित भविष्य के लिए प्राकृतिक संसाधनों और जैव विविधता के संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला जा सके। यह दिवस वायु, जल, भूमि, वन, वन्यजीव और समग्र पर्यावरणीय स्वास्थ्य के संरक्षण हेतु जागरूकता और कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है।

• विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस का मुख्य उद्देश्य वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए एक स्थायी पर्यावरण सुनिश्चित करने के लिए वायु, जल, मिट्टी, वनस्पतियों, जीवों और ऊर्जा सहित पृथ्वी के सीमित प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा और कुशलतापूर्वक प्रबंधन की तत्काल आवश्यकता के बारे में वैश्विक जागरूकता पैदा करना है।

• यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस जिम्मेदार उपभोग पैटर्न और संरक्षण प्रयासों, नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग और प्रदूषण में कमी को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देता है, विशेष रूप से बिगड़ते जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय गिरावट के संदर्भ में।

• विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर्यावरणीय स्थिरता के व्यापक ढाँचे के अंतर्गत मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) तथा अन्य वैश्विक पर्यावरणीय ढाँचों के अनुरूप है। यह प्रकृति के संरक्षण हेतु राष्ट्रों, संस्थाओं और व्यक्तियों की सामूहिक ज़िम्मेदारी को रेखांकित करता है।

Key Points:-

(i) इस दिवस की शुरुआत जून 1972 में हुई थी, जब स्वीडन के स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस ऐतिहासिक सम्मेलन के परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) समर्थित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) का गठन हुआ और 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के रूप में औपचारिक रूप से नामित किया गया।

(ii) 2025 में WNCD का पालन चल रही वैश्विक जलवायु वार्ताओं और पारिस्थितिकी तंत्र बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक (2021-2030) के प्रकाश में अतिरिक्त प्रासंगिकता रखता है।

(iii) यह दिन पर्यावरण न्याय, वन बहाली, वन्यजीव संरक्षण और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के लिए वैश्विक आंदोलनों का भी पूरक है।

2. वैश्विक बाघ दिवस 29 जुलाई 2025 को मनाया गया।

वैश्विक बाघ दिवस 2025, जो प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है, का उद्देश्य दुनिया भर में जंगली बाघों की आबादी में आई तीव्र गिरावट पर प्रकाश डालना है—जो 20वीं सदी की शुरुआत में लगभग 1,00,000 थी, आज घटकर लगभग 4,000 रह गई है। यह दिवस जागरूकता, नीतिगत कार्रवाई और आवास संरक्षण के माध्यम से बाघों के संरक्षण के लिए एक एकीकृत वैश्विक प्रयास का प्रतीक है।

• इस दिवस की स्थापना 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग बाघ शिखर सम्मेलन में की गई थी, जहां 13 बाघ-क्षेत्र वाले देशों के प्रतिनिधियों ने TX2 लक्ष्य - 2022 तक जंगली बाघों की आबादी को दोगुना करने - के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। हालांकि सभी देश इसे हासिल नहीं कर पाए, लेकिन इसने समन्वित वैश्विक बाघ संरक्षण के लिए एक मिसाल कायम की।

• जंगली बाघों को अवैध शिकार, वनों की कटाई, आवास विखंडन और अवैध वन्यजीव व्यापार जैसे गंभीर खतरों का सामना करना पड़ रहा है। इन कारकों के साथ-साथ बढ़ते मानव-वन्यजीव संघर्ष ने उनके आवासों को काफी हद तक कम कर दिया है, जिससे कई क्षेत्रों में बाघ विलुप्त होने के कगार पर पहुँच गए हैं।

Key Points:-

(i) भारत बाघ संरक्षण में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बना हुआ है, और 2022 की बाघ गणना के अनुसार वर्तमान में यहाँ 3,682 बाघ हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) के नेतृत्व में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत किए गए प्रयासों से भारत को समय से पहले ही TX2 लक्ष्य हासिल करने में मदद मिली है, जिससे देश भर में 53 बाघ अभयारण्यों का प्रबंधन संभव हो पाया है।

(ii) वैश्विक बाघ दिवस 2025 पर, भारत में बाघों के आवासों और चिड़ियाघरों में जागरूकता अभियान चलाए गए। कार्यक्रमों में मैराथन, छात्र रैलियाँ, फेस

पेंटिंग और #GlobalTigerDay और #SaveTheTiger जैसे हैशटैग का उपयोग करते हुए डिजिटल अभियान शामिल थे, जिससे बाघ संरक्षण प्रयासों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ।

3. विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2025 विश्व स्तर पर 28 जुलाई को मनाया गया।

हाल ही में 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस (WHD) 2025 मनाया गया, जिसका उद्देश्य वायरल हेपेटाइटिस के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है—एक गंभीर यकृत संक्रमण जो यकृत रोग और कैंसर का कारण बन सकता है। इस वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के नेतृत्व में "हेपेटाइटिस: आइए इसे तोड़ें" विषय पर 15वाँ आधिकारिक दिवस मनाया गया।

• विश्व हेपेटाइटिस दिवस प्रतिवर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है ताकि वायरल हेपेटाइटिस, जो एक प्रमुख वैश्विक स्वास्थ्य समस्या है, से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डाला जा सके।

• यह कार्यक्रम निवारक देखभाल, शीघ्र निदान और उपचार तक पहुँच को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। यह नीति निर्माताओं, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और आम जनता को एक साथ लाता है ताकि 2030 तक हेपेटाइटिस को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में समाप्त करने की दिशा में प्रगति में तेज़ी लाई जा सके।

• विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2025 का विषय, "हेपेटाइटिस: आइए इसे तोड़ें", उन अनेक बाधाओं—वित्तीय, सामाजिक, प्रणालीगत और कलंक-संबंधी—को दूर करने पर ज़ोर देता है जो हेपेटाइटिस उन्मूलन और यकृत कैंसर की रोकथाम में बाधा डालती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) सरकारों और नागरिक समाज से हेपेटाइटिस सेवाओं को सुलभ और कलंक-मुक्त बनाने के लिए जन स्वास्थ्य रणनीतियों को मज़बूत करने का आह्वान करता है।

Key Points:-

(i) इस वर्ष, 28 जुलाई, 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा समन्वित विश्व हेपेटाइटिस दिवस का 15वाँ आधिकारिक आयोजन किया गया। यह दिवस नोबेल पुरस्कार विजेता डॉ. बारूक ब्लमबर्ग की जयंती के साथ जुड़ा है, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी और पहला टीका विकसित किया था।

(ii) विश्व हेपेटाइटिस दिवस का पहला वैश्विक आयोजन 19 मई, 2008 को हुआ, जिसकी शुरुआत विश्व हेपेटाइटिस एलायंस द्वारा की गई, जो रोगी समूहों के सहयोग से काम करने वाला एक गैर-लाभकारी संगठन है।

(iii) मई 2010 में, 63वीं विश्व स्वास्थ्य सभा (WHA) ने जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में आधिकारिक रूप से प्रस्ताव WHA63.18 को अपनाया, जिससे 28 जुलाई को इस दिवस के लिए स्थायी तिथि बना दी गई। पहला WHO-मान्यता प्राप्त विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई 2011 को मनाया गया था।

SCIENCE AND TECHNOLOGY

1. स्टारडॉर ने IISc बेंगलुरु में भारत के पहले हाइड्रोजन-ऑक्सीजन प्रणोदन इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।

जुलाई 2025 में, बेंगलुरु स्थित भारतीय अंतरिक्ष-तकनीक स्टार्टअप, स्टारडॉर एयरोस्पेस टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड ने भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), कर्नाटक में भारत के पहले हाइड्रोजन-ऑक्सीजन प्रणोदन इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण करके एक बड़ी सफलता हासिल की। यह नवाचार स्वच्छ, पुन: प्रयोज्य अंतरिक्ष प्रणोदन प्रणालियों की ओर देश के परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

• स्टारडॉर का हाइड्रोजन-ऑक्सीजन प्रणोदन इंजन पूरी तरह से भारत में ही विकसित किया गया था, जो भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती तकनीकी आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। यह परीक्षण भारत के प्रमुख वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों में से एक, भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु के साथ साझेदारी में किया गया था।

• प्रणोदन इंजन अपने प्रणोदकों के रूप में गैसीय हाइड्रोजन और गैसीय ऑक्सीजन का उपयोग करता है। ये तत्व उच्च दक्षता और स्वच्छ दहन के लिए जाने जाते हैं, जो इन्हें भविष्य-केंद्रित अंतरिक्ष अभियानों के लिए उपयुक्त बनाता है। इन हरित प्रणोदकों का चयन सतत एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की दिशा में वैश्विक प्रयासों के अनुरूप है।

Key Points:-

(i) इस इंजन की एक प्रमुख विशेषता इसका पर्यावरण-अनुकूल उत्सर्जन है। दहन के दौरान यह केवल जल वाष्प छोड़ता है, जिससे यह शून्य-कार्बन उत्सर्जन प्रणाली बन जाती है। यह भारत को अंतरिक्ष अभियानों के लिए स्वच्छ प्रणोदन तकनीक विकसित करने वाले कुछ देशों में शामिल करता है।

(ii) यह इंजन विशेष रूप से स्टारडॉर के आगामी लुकास ऑर्बिटल ट्रांसफर व्हीकल (OTV) को शक्ति प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसे 2027 में लॉन्च करने की योजना है। लुकास OTV कक्षाओं के बीच पेलोड और उपग्रहों के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे अंतरिक्ष में सटीक रसद और तैनाती में सहायता मिलेगी।

(iii) लुकास, एक पुन: प्रयोज्य वाहन के रूप में, अंतरिक्ष में उपग्रह सेवा और मॉड्यूलर तैनाती में सहायता प्रदान करने की स्टारडॉर की महत्वाकांक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। इस इंजन के साथ, लुकास प्रक्षेपण यान के प्रक्षेपण बिंदु से उपग्रह की अंतिम इच्छित कक्षा तक पेलोड पहुँचाने में सक्षम होगा—जिससे भारत के वाणिज्यिक अंतरिक्ष क्षेत्र की दक्षता में सुधार होगा और मिशन क्षमताओं का विस्तार होगा।

2. चीन ने WAIC 2025 में AI विकास और सुरक्षा के बीच संतुलन के लिए वैश्विक सहमति की वकालत की।

जुलाई 2025 में, शंघाई में आयोजित विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन (WAIC) के दौरान, चीन जनवादी गणराज्य ने प्रधानमंत्री ली कियांग के माध्यम से, ज़िम्मेदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के विकास पर वैश्विक सहमति की तत्काल आवश्यकता पर ज़ोर दिया। चीन ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से AI से संबंधित सुरक्षा जोखिमों और शासन संबंधी चुनौतियों का मिलकर समाधान करने का आग्रह किया।

• चीन के शंघाई में आयोजित विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन (WAIC) के 2025 संस्करण में, प्रधानमंत्री ली कियांग ने एक मुख्य भाषण दिया और संभावित सुरक्षा खतरों के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता नवाचार के लाभों को संतुलित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। इस कार्यक्रम का आयोजन चीन जनवादी गणराज्य के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शंघाई नगर सरकार और प्रमुख कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान निकायों के साथ मिलकर किया था।

• ली कियांग ने इस बात पर ज़ोर दिया कि AI को मानवीय नियंत्रण और शासन ढाँचे के तहत विकसित होना होगा। उन्होंने डीपफेक, मशीनी भ्रम और एल्गोरिथम संबंधी भेदभाव से जुड़ी वैश्विक चिंताओं का ज़िक्र करते हुए इन्हें एक ज़रूरी मुद्दा बताया जिसके लिए एक एकीकृत वैश्विक रणनीति की ज़रूरत है। उन्होंने एआई तकनीकों को सभी देशों के लिए सुरक्षित, विश्वसनीय और समावेशी बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के प्रति चीन के समर्थन की पुष्टि की।

• चीन ने अपनी वैश्विक AI गवर्नेंस पहल का भी प्रदर्शन किया, जिसे पहली बार 2023 में पेश किया गया था, और इसने सर्वसम्मति से संचालित, नैतिक एआई के निर्माण में राजनयिक प्रयासों का नेतृत्व करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। यह पहल जोखिम मूल्यांकन, ओपन-सोर्स विकास और संयुक्त राष्ट्र, जी20 और विश्व आर्थिक मंच को शामिल करते हुए बहुपक्षीय विनियमन के लिए सीमा पार समन्वय का प्रस्ताव करती है।

Key Points:-

(i) हुआवेई, टेनसेंट, अलीबाबा जैसी अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों और टेस्ला, अमेज़न और एनवीडिया जैसी वैश्विक कंपनियों ने WAIC 2025 में भाग लिया। प्रदर्शनी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) से संचालित रोबोटिक्स, भाषा मॉडल और साइबर सुरक्षा प्रणालियाँ शामिल थीं। चीन ने खुद को अच्छे के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के समर्थक के रूप में स्थापित किया, डेटा के उपयोग में पारदर्शिता और एल्गोरिदम में तटस्थता को बढ़ावा दिया।

(ii) प्रधानमंत्री ली कियांग की टिप्पणी जनरेटिव AI, स्वायत्त हथियारों और AI-संचालित निगरानी जैसी अग्रणी AI प्रणालियों को विनियमित करने की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय मांगों के अनुरूप है। चीन ने तकनीकी दिग्गजों के एकाधिकार को रोकने के लिए एक वैश्विक आचार संहिता बनाने का आग्रह किया, खासकर वैश्विक दक्षिण में, जहाँ डिजिटल विभाजन एआई की निष्पक्षता के लिए खतरा पैदा करते हैं।

(iii) WAIC 2025 का समापन एक अंतर्राष्ट्रीय AI गवर्नेंस फ्रेमवर्क के प्रस्ताव के साथ हुआ, जिसे चीनी, यूरोपीय और आसियान प्रतिनिधियों ने सह-लिखा था। इस दस्तावेज़ में एक AI सुरक्षा परिषद के गठन, AI साक्षरता के लिए धन मुहैया कराने और AI नैतिकता एवं जवाबदेही प्रगति पर संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक,

वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) को वार्षिक रिपोर्ट देने का सुझाव दिया गया है।

BOOKS & AUTHORS

1. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में छात्र कल्याण पर पुस्तक का शुभारंभ किया।

26 जुलाई 2025 को, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास सभागार में "छात्रों का सतत कल्याण: उच्च शिक्षा में एक सामूहिक उत्तरदायित्व" नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक छात्रों के कल्याण और उच्च शिक्षा सुधार के लिए समग्र दृष्टिकोण पर ज़ोर देती है।

- **यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास सभागार में आयोजित किया गया, जहाँ मुख्यमंत्री धामी ने उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा छात्रों की मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक चुनौतियों का समाधान करने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने विश्वविद्यालयों से व्यापक कल्याणकारी रणनीतियाँ अपनाने का आग्रह किया और कहा कि शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए।**

- **"छात्रों का सतत कल्याण: उच्च शिक्षा में एक सामूहिक उत्तरदायित्व" नामक पुस्तक, लता पांडे और नीति अनुसंधान केंद्र, नई दिल्ली के निदेशक डॉ. रामानंद द्वारा सह-संपादित है। यह भारत में छात्र कल्याण को बढ़ावा देने हेतु नीतिगत ढाँचों और संस्थागत उत्तरदायित्वों का अन्वेषण करती है। मुख्यमंत्री धामी ने इसकी पहुँच बढ़ाने के लिए इसके हिंदी अनुवाद का भी प्रस्ताव रखा।**

Key Points:-

(i) विज्ञप्ति के अवसर पर बोलते हुए, धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) को लागू करने वाले पहले भारतीय राज्य के रूप में उत्तराखंड की प्रशंसा की। उन्होंने शिक्षा के ऐसे परिवेश को विकसित करने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता दोहराई जहाँ छात्रों का कल्याण और कौशल विकास साथ-साथ चलते हैं।

(ii) इस अवसर पर उपस्थित रेक्टर अधिकारियों में उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक प्रो. कमल किशोर पांडे और कुमाऊँ विश्वविद्यालय के डीएसबी परिसर में गृह विज्ञान विभागाध्यक्ष प्रो. लता पांडे, डॉ. रामानंद भी शामिल थे। धामी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि उच्च शिक्षा संस्थानों को केवल शैक्षणिक परिसर के रूप में नहीं, बल्कि ज्ञान और कल्याण के केंद्र के रूप में कार्य करना चाहिए।

ENVIRONMENT

1. ZSI ने पश्चिम बंगाल में भारत की पहली पिराटुला वुल्फ स्पाइडर और मेघालय में दो नई सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण मेंढक प्रजातियों की खोज की।

जुलाई 2025 में, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (Zoological Survey of India – ZSI) के वैज्ञानिकों ने Piratula acuminata की खोज की, जो भारत में पिराटुला वुल्फ स्पाइडर की पहली रिकॉर्ड की गई प्रजाति है। यह खोज पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा में हुई। इसके साथ ही, मेघालय की पहाड़ियों में दो सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण मेंढक प्रजातियाँ — Raorchestes jajoid और Raorchestes jadoh की भी खोज की गई, जो भारत की जैव विविधता को दर्शाती है।

- **भारत में पहली बार पाई गई पिराटुला वुल्फ स्पाइडर: यह नई प्रजाति Piratula acuminata ल्यकोसिडे (Lycosidae) परिवार से संबंधित है, जिसे आमतौर पर वुल्फ स्पाइडर कहा जाता है। यह भारत में पिराटुला जीनस की पहली रिकॉर्ड की गई प्रजाति है, जो पहले केवल एशिया, यूरोप और उत्तर अमेरिका में पाई जाती थी।**

- **यह मकड़ी पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा के सागर द्वीप में पाई गई, जो कि यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त एक विश्व धरोहर स्थल है। यह क्षेत्र पहले से ही बाघों, खारे पानी के मगरमच्छों और अद्वितीय अकशेरुकी प्रजातियों का निवास है।**

- **यह मकड़ी लगभग 8 से 10 मिमी लंबी होती है, जिसका रंग हल्का क्रीम होता है। इसके शरीर पर चॉक जैसे सफेद धब्बे और पिछले हिस्से पर हल्के भूरे रंग की धारियाँ पाई जाती हैं, जो इसे आर्द्रभूमियों में छिपने में मदद करती हैं।**

Key Points:-

(i) इस प्रजाति की खोज को 7 जुलाई 2025 को अंतरराष्ट्रीय जर्नल Zootaxa में प्रकाशित किया गया, जो ZSI के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया एक महत्वपूर्ण टैक्सोनॉमिक योगदान है।

(ii) मेघालय में दो सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण मेंढक की खोज: Raorchestes jajoid और Raorchestes jadoh नामक मेंढक प्रजातियाँ मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स में खोजी गईं। यह खोज असम डॉन बॉस्को विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं वर्जरी और मधुरीमा दास द्वारा की गई और इनका प्रकाशन Journal of Threatened Taxa में हुआ।

(iii) मेंढकों के नाम खासी संस्कृति और स्थलाकृति पर आधारित: Raorchestes jadoh का नाम 'जादोह' नामक खासी व्यंजन पर रखा गया है, जबकि Raorchestes jajoid का नाम खासी भाषा के शब्द 'जाकोइड' से लिया गया है, जिसका अर्थ है "मेंढक"। Raorchestes jajoid को 815 मीटर की ऊंचाई पर लैतृंगेव के पास खोजा गया, जबकि Raorchestes jadoh को 1,655 मीटर की ऊंचाई पर लैंगटोर के पास पाया गया।

Static GK

Indian Railways (IR)	मंत्री: अश्विनी वैष्णव	मुख्यालय: नई दिल्ली
Maldives	अध्यक्ष: मोहम्मद मुइज़्ज़ू	मुद्रा: मालदीवियन रूफिया
Meghalaya	मुख्यमंत्री (CM) : कॉनराड संगमा	राज्यपाल : चन्द्रशेखर एच. विजयशंकर
Hockey India	अध्यक्ष : दिलीप तिर्की	मुख्यालय: नई दिल्ली
Andhra Pradesh	मुख्यमंत्री: एन. चंद्रबाबू नायडू	राज्यपाल: सैयद अब्दुल नज़ीर
Turkey	राजधानी: अंकारा	मुद्रा: तुर्की लीरा
RBI	राज्यपाल: संजय मल्होत्रा	मुख्यालय: मुंबई
Odisha	मुख्यमंत्री: मोहन चरण माझी	राज्यपाल: हरि बाबू कंभमपति
China	राष्ट्रपति: शी जिनपिंग	आधिकारिक भाषाएँ: मंदारिन, पुतोंगहुआ